

at the same time, the manufacture of formulations does not become an uneconomic operation for the formulators on an overall basis.

(vi) Action has been initiated to implement the decision of the Government on the recommendations of the Hathi Committee on the use of brand names. These decisions are contained in Paragraph 71.1 to 71.6, 99, 100 and 102 of the Statement laid on the Table of the Rajya Sabha on the 24th of April, 78.

**रेलवे स्टेशनों पर कैंटीनों तथा खोमबे लगाना के ठेके**

1414. श्री हरि शंकर भाभड़ा :

श्री कलराज मिश्र :

श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर कैंटीनों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय के लिए सामान्यतया कितनी अवधि के लिए ठेके दिये जाते हैं;

(ख) क्या ऐसे ठेके देने के मामले में सहकारी समितियों, बेरोजगार स्नातकों एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

[Contracts for canteens and vendors at railway station

1414. SHRI HARISHANKAR BHABHDA:  
SHRI KALRAJ MISHRA;  
SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the period for which contracts for canteens and vending at the railway stations are normally given;

(b) whether there is any proposal under Government's consideration to give priority to cooperative societies unemployed graduates and economically weaker sections of the society in the matter of giving these contracts; and

(c) if so, what are the details thereof?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) वेडिंग के ठेके 3 वर्ष की अवधि के लिए, तथा उपाहारगृहों और रेस्टोरेंटों के ठेके 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किये जाते हैं। यदि उनका काम सन्तोषजनक हो तो अगली एक अवधि के लिए ठेके का नवीकरण कर दिया जाता है।

(ख) और (ग) पहले से ही ऐसे निर्देश मौजूद हैं कि खान पान/विक्रय के ठेके आवंटित करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों, बेरोजगार स्नातकों, सहकारी समितियों, महिला समितियों, स्वतन्त्रता सेनानियों और अन्य स्वयंसेवी संगठनों को तरजीह दी जाये।

[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Vending contracts are allotted for a period of three years and Refreshment Rooms and Restaurants for five years. If the performance is found to be satisfactory the contract is renewed for further term.

(b) and (c) Instructions already exist that persons belonging to Scheduled Castes|Scheduled Tribes, co-operative Societies, Mahila Samities, Freedom fighters and other Voluntary Organisations should be given preference in the allotment of catering|vending contracts.]